Deteriorating Law and Order situation in Madhya Pradesh

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : महोदया, आपके द्वारा इस सदन को यह सूचित करते हुए मुझे अत्यंत दुख है, क्षोभ है कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार बम विस्फोटों की घटनाएं हुई हैं । बम विस्फोट यहां अब साधारण बात बन गई है और एक आम बात बन गई है । आज लगातार देश के अंदर विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं । बम विस्फोटों का संबंध देश और प्रदेश के लॉ एंड आर्डर से है और मैं समझता हूं कि सरकार ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए । लेकिन अभी तक जितने समाचार हैं उनसे ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस मामले में गंभीर है या बम विस्फोट करने वालों को या उनसे जिनका संबंध है उनका पता लगाकर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही कर रही हो, ऐसा दिखाई नहीं देता । महोदया, बंबई की घटना के बाद, बंबई की बम विस्फोट की घटनाएं कितनी चिन्ता का विषय रही है और इस बात का खेद रहा है कि अपराधियों में कुछ का तो पता लगा लिया है लेकिन अभी तक अपराधियों को पूरी तरह पकड़ा नहीं गया है, न उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो रही है और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इन मामलों को दबाया जा रहा है । दुर्भाग्य इस बात का है कि अपराधी राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं और इन्हें दुर्भाग्य से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है । इस वजह से बिना रूकावट और लगातार एक के बाद एक घटनाएं सारे देश में हो रही हैं । मैं अन्य प्रदेशों का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ही इसी जुलाई के महीने में, एक महीने में लगातार 9 दिन बम विस्फोट की घटनाएं हुई हैं यह भी अकेले भोपाल शहर में 9 बम विस्फोटों की घटनाएं हुई और कुछ स्थान ऐसे हैं कि एक ही स्थान पर दो दो बार बम विस्फोट हुए हैं । लेकिन आज तक अपराधियों का पता नहीं लगा है न उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है । न केन्द्रीय गृह मंत्रालय इस बारे में गंभीर है । मैं समझता हूं कि सारे प्रदेश के अंदर कोई कानून और व्यवस्था नहीं है और शायद इसकी वजह यह है कि वहां पर अभी कोई पापुलर गवर्नमेंट नहीं है । राज्यपाल महोदय का शासन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर राज्यपाल को जैसाकि अभी और स्थानों का वर्णन आया, मध्य प्रदेश के अंदर भी खिलौना बनाकर रखा है । मध्य प्रदेश में कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है । प्रशासन ठप्प हो चुका है, उसकी वजह यह है कि पिछले दो महीनों में करिब एक लाख ट्रांसफर्स हुए हैं । मुझे ट्रांसफर्स से कुछ लेना देना नहीं है, आवश्यक होंगे तो ट्रांसफर्स भी करने पड़ेंगे लेकिन एक लाख ट्रांसफर जो मध्य प्रदेश में किए गए हैं उसके पीछे दुर्गंध रहा है, और उसके पीछे संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि लेन देन हो रहा है । पहले ट्रांसफर करने के लिए पैसा लिया गया है जहां पर अपने चहेतों को भेज दिया गया है, इस बात की परवाह नहीं है कि वहां कोई उपयुक्त है या नहीं ? भारी संख्या में उनकी ट्रांसफर कर दी गई, और आतंक फैला दिया गया । जब आतंक पैदा हो गया फिर उनसे पैसे ले-दे कर उनकी ट्रांसफर रद्द की जा रही है । गर्व यह है कि प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है । सारे कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं । भोपाल के अंदर जो कुछ, इतवारे के अंदर, मंगलवारे में, शाहजानाबाद की बजरिया में और वहां के प्रमुख बस स्टैंड पर 9 बम विस्फोटों की घटनाएं हुई, 11 डकैतियों की घटनाएं हुई । एक महीने के अंदर यह हालत मध्य प्रदेश के अंदर बन गई है । मैं गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई कार्य योजना इन्होंने बनाई है इन बम विस्फोटों की घटनाओं को रोकने के लिए या उनका पता लगाने के लिए ? किस प्रकार की बम विस्फोटों की घटनाएं हुई है यह कोई साधारण बम विस्फोट नहीं हैं । ऐसा लग रहा है कि बाहर से सामग्री आ रही है । उनका लिंक दूर-दूर तक है । पैसा बाहर से आ रहा है । लेकिन इन सब को रोकने के लिए सरकार की कोई मशीनरी काम नहीं कर पा रही है, न कर रही है । मैं इसकी निन्दा करना चाहता हूं । साथ ही मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश में जो बम विस्फोट हुए, नरसिंह गढ़ में बम विस्फोट हुए, उज्जैन में हुए, भोपाल में लगातार जारी है, लोग हलाक हुए हैं, कोई गम्भीर कार्रवाई करेगा ।

भोपाल में यह हुआ कि कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल तक के तबादले कर दिये गये जिनके पीछे कोई कारण नहीं था । अपराधियों को पहचानने वाले अधिकारी आज भोपाल में मौजूद नहीं हैं । सबसे भारी हेराफेरी हुई है ट्रांसफर के मामले में इसलिए भोपाल में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है । ला एंड आर्डर समाप्त हो गया है । हम गृह मंत्री जी से यह आशा करते हैं कि वह कोई कार्य योजना बनायेंगे, कोई एजेंसी नियुक्त करेंगे ताकि मध्य प्रदेश में बम विस्फोटों को रोकने में, अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके । यह पता लगाये कि इनके किन-किन से लिंक हैं, कहां-कहां से पैसा आ रहा है, कहां-कहां से बम आ रहे हैं । आज में इन सब बातों से किसी को परिचित नहीं कराया गया, यह चिंता का विषय है । मैं आशा करता हूं गृह मंत्रालय इस मामले में कोई गम्भीर कार्रवाई करेगा । धन्यवाद ।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : यह कहा गया कि पैसा ले-दे कर ट्रांसफर रद्द हुए हैं इसको कार्रवाई से निकाला जाए क्योंकि यह गवर्नर की कार्य प्रणाली पर आक्षेप है ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : पूरी कौंसेली पर कहा है ।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : मैंने कोई गवर्नर के लिए नहीं कहा । आम बात कही है जो अखबारों में कांग्रेस वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ।

SHORT DURATION DISCUSSION

Recent Verdict of the Swiss Supreme Court Relating to Bofors

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Now we shall take up the Short Duration Discussion. Shri P. Upendra

will raise the discussion on the recent verdict of the Swiss Supreme Court relating to Bofors.

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): Madam Vice-Chairman, we are once again discussing the Bofors issue. I do not recollect how many times we discussed it in this House and the other House. Despite the calculated and sustained efforts by the ruling Congress Party to lay the ghost of Bofors to rest, it continues to haunt them. Now a great breakthrough has come in the 6-year long investigation into this controversy when the Swiss Justice Ministry released, on July 22, the names of five individuals and two companies, following the judgment of the Federal Court of Switzerland, upholding India's Letter Rogatory and the charges contained in it. Apart from the Hinduja brothers and Win Chadha... *(Interruptions)*.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आपको समय मिलेगा अगर आपकी पार्टी ने आपका नाम दिया है, तो उस समय आप इस चीज पर बोल सकती हैं। अभी इनको आप बोलने दीजिए।

SHRI P. UPENDRA: Apart from Hinduja brothers and Win Chadha, the name of Ottavio Quattrocchi also figures in this list thus unravelling the mysterious 'Qs' and 'Rs' in the Martin Ardbo diary which, at that time, we did not know what they meant. I will come to this aspect a little later.

For over six years, since the explosive Swedish Radio broadcast of 16th April 1987, the Bofors scandal has been very much a part of our political vocabulary. It became the main election issue in 1989 and resulted in unseating the Government headed by Mr. Rajiv Gandhi.

If you go through the records of this House and the other House, you will find that, from the beginning, a crude and clumsy effort was made to suppress truth and to protect politicians and key defence personnel who were accused of receiving bribes for awarding the gun contract to Messrs. Bofors of Sweden, on March 24, 1986.

Madam, if you recollect, when the Swedish Radio broadcast the news, what was the reaction? Normally, any responsible Government would have reacted to it by saying 'We have got the information. We will investigate and take appropriate action'. Instead, the Congress Party and the Government, at that time, reacted by charging the foreign radio of trying to destabilise the nation. When the reaction was being drafted by the present Prime Minister, I happened to be there. When I asked him why they were reacting in this manner and coming to the conclusion that the broadcast of a foreign radio was meant to destabilise the nation, he just looked at me. Now, I find that the same language was used recently in relation to another charge made against the present Prime Minister, that it was meant to destabilise the nation. This is how they reacted from the beginning.

Then, on April 24, 1987, the then Defence Minister, Mr. K. C. Pant, made a statement in Parliament that there were neither any middlemen in the Bofors gun contract, nor were any commission paid to them. After that, when we go through the records of the House, we find that there were many shifting statements made by the Government on various occasions. They first said that there were no middlemen at all. The second phase was, even if there were some middlemen, they were not paid any commission. Then, they said, even if some money had been paid to some middlemen, it was not by way of commission, but mainly as winding-up charges. Then, they said, even if some commission had been paid, it was not paid to any Indian. Then, they said, even if the persons to whom commission was paid were Indians, they did not have any links with politicians. Finally, to climax it all, the then Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi, had to confess in the House and say that he or any of his family members did not receive any bribe.

SHRI M. A. BABY (Kerala): Mr. Upendra, if you permit me, I would like to point out that at one stage, the then Prime Minister also said that some commission would be paid for genuine services.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, you said that interruptions would not be allowed. How did you allow him then?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप तो बोलने वाली हैं, उन्होंने सिर्फ एड किया है।

SHRI P. UPENDRA: I thank Mr. Baby for adding one more statement of the then Prime Minister. They also said that if any commission had been paid for genuine services, there was nothing wrong in that. This also they said.

Therefore, from the beginning, the House was taken for a ride. The nation was taken for a ride.

Untruths were uttered. To cover one untruth, they uttered more untruths. The Swedish National Audit Bureau report subsequently confirmed illegal payments made to the agents in the Swiss bank accounts. They said that the amount was only Rs. 64 crores, but according to unofficial figures, I think the money which changed hands was about Rs. 600 crores. And there were more revelations in the newspapers before that and after that also. Particularly, I should congratulate the papers like the 'Hindu', the 'Indian Express' and the 'Statesman' who did a remarkable job which even CBI or any other Government agency could not do. Even the investigative journalist Smt. Chitra Subramaniam deserves the gratitude of the nation for bringing out the truth. Then, the Comptroller and Auditor General of India, in his report, has lent further credence to the charge of bribery in the Bofors scandal. He happens to be an hon. Member of this House now. He also deserves the gratitude of the nation for withstanding the pressure from the Government and for giving an objective report.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: And then joining the BJP.

SHRI P. UPENDRA: All good people go there.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): All the people who are rejected from other political parties go to the BJP. ...*(Interruptions)*

SHRI P. UPENDRA: Madam, a Joint Parliamentary Committee was then appointed. You may recall that the Opposition gave some suggestions in regard to the terms of reference, some very valid suggestions which would have made the enquiry effective, but the Government did not accept them and as a result, the Opposition had to boycott the Joint Parliamentary Committee. And in the history of the Parliament we have never seen a Parliamentary Committee acting in such a partisan manner, trying to conceal the truth instead of unravelling the truth, and Mr. Shankaranand deserves credit for all that.

And the recent revelations clearly demonstrate that the Joint Parliamentary Committee on Bofors misled this Parliament, concealed the truth and tried to exonerate the culprits. Then came the National Front Government. Many people ask why the National Front Government could not succeed in unravelling the truth in spite of the promises made by the then Prime Minister. *(Interruptions)*. Do not disturb. You have a chance. You will have a chance to rebut, if you want. So, there was a charge why Mr. V. P. Singh could not fulfil his promise that within 15 days he would reveal the names. Madam, the House would recall that but for the defeat of the Congress Party in 1989 elections and the formation of the National Front Government, this Bofors issue would have died. It was only during that Government that some progress was made. It goes to the credit of the National Front Government that firm and steady steps were taken to continue investigations which have paved the way for ultimately bringing out the truth. For the first time, an FIR was filed on January 22, 1990. A letter rogatory was sent to the Swiss authorities and the CBI was allowed to interrogate the then Managing Director of Bofors, Mr. Martin Ardbo. Some accounts in the Swiss Banks were frozen on January 26, 1990 by filing an application before the Swiss Investigating Judge. Section 16(a) of the Criminal Procedure Code was amended and on India's request the Swiss Investigating Judge decided to assist India. These were the steps taken by the National Front Government and because of this only the enquiry progressed and was allowed to progress, some information could come today which will lead to further unravelling the truth.

Madam, I have got to make a small comment on the role of the CBI in this connection. All this progress was made despite the dilatory stand taken by the CBI at that time. Even some of the officers who are no longer with the CBI have testified to the pressures on them and today they want to co-operate with the Government by giving some more information. So, the CBI's role has been dubious. The machinery was completely paralyzed—I don't blame the officers because they were acting under the instructions of the Government—during the earlier Congress regime. I don't deny that such attempts were made in the National Front Government's time also—I don't want to go into them—but they were effectively repulsed and the then Prime Minister, Mr. V. P. Singh, withstood all these pressures and gave clear-cut directives to the officials, and the investigation was continued. The beneficiaries of these kickbacks made several attempts subsequently also through their appeals in Cantonal Courts in Zurich and Geneva and the Swiss Federal Court to prevent passage of documents to the Government of India. But these appeals were

dismissed and the documents relating to AE Services reached India in December 1990. Then again, another attempt was made by the Congress Party which supported the Government headed by Chandra Shekhar ji. Though one Minister was particularly trying to help them, Chandra Shekhar ji withstood the pressure. The investigation was not dropped and it was continued.

Madam, the Swiss Federal Court gave a judgment after the fall of the National Front Government, and it had three significant implications. Firstly, the theory of winding-up charges was negatived. Secondly, the principle that payment of commission was bribe was established. And, thirdly, the way for handing over the bank documents to Indian investigating agencies was paved and the veil of confidentiality was removed. These are the three implications of that judgment. Meanwhile the Congress Party came back and we know that pressure was brought on the present Prime Minister also to drop it—and the pressure continues even today. If you have seen the resolution of the Congress Working Committee, the Congress Parliamentary Party's Executive Committee, etc., and the recent outcry that the Prime Minister has not effectively repelled the charges against Mr. Rajiv Gandhi—they were passing a resolution again—all these indicate browbeating tactics and pressure tactics applied on the Prime Minister. They also made a crude attempt through a letter which was passed on to the Swedish authorities through Mr. Solanki who had to pay a heavy price for his indiscretion.

Madam, now information has come from Switzerland that as many as seven parties were trying to block the disclosure of the names of those who received the kickbacks of the money from Bofors. There is a fear among the Congress circles and there is pressure to stall further investigation. The Government also has not taken enough follow-up measures now after the names have been revealed. Some steps have to be taken immediately to further its progress.

Initially, I mentioned that among the names was one of Mr. Quattorochi. He has, of course, denied the whole thing. But one of the aspects which is under investigation, which will be under investigation, by the Swiss authorities, as well as the Swedish authorities, is why a person representing a private company which had nothing to do with the procurement of this gun, had to file an appeal for not revealing the names. He has to explain why he had to do it and what business he has got to interfere in this affair. I don't want to make any charges, particularly against those leaders who are dead and gone and who have become martyrs or whatever it is, but it is well known that Mr. Quattorochi has a 20-year long association with the family of Mr. Gandhi and, whatever you may say, unless this matter is cleared sufficiently, the needle of suspicion will be directed towards 10, Janpath.

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra) : You have to prove that.

SHRI P. UPENDRA : It is likely, I said.

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): How has he come to this conclusion? ... *(Interruptions)*

MISS SAROJ KHAPARDE: Who are you ? .... *(Interruptions)*

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सरोज जी, क्या आपकी पार्टी से अहलूवालिया जी बोलने वाले हैं ... **(व्यवधान)**

श्री एस० एस० अहलूवालिया : मैं तो बोलने वाला हूं । मैं तो बोलूंगा । इस तरह के सवाल क्यों करते हैं । यह कोई तरीका नहीं है बात करने का ... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): He is not coming to the conclusion.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : क्या कोर्ट के निर्णय में इन बातों का हवाला है ? ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सरोज जी, ... **(व्यवधान)** आपको भी बोलना है ... **(व्यवधान)**

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): What is the relationship of Mr. Quattrocchi with 10, Janpath ?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : कोई ऐसी बात वक्तव्य में नहीं कही है । अगर उसी बात पर आप बात करना चाहते हैं तो अपने भाषण में करिये ... **(व्यवधान)** आप बैठिये ।

SHRI S. S. AHLUWALIA : He may be your son-in-law.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): He is your uncle-in-law.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : इनके तुरंत बाद अहलुवालिया जी हैं . . . (व्यवधान)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): What is your point of order?

She is raising a point of order.

करने दीजिए ना, सारे बोलेंगे तो मैं कैसे प्वाइंट आफ आर्डर सुनूंगी ।

MISS SAROJ KHAPARDE: Madam, I would like to request one thing. Mr. Upendra said that No. 10, Janpath was involved.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : नाम ही नहीं लिया है । दस जनपथ कब कहा है . . . (व्यवधान)

SHRI P. UPENDRA: No, I did not say that.

SHRI S. S. AHLUWALIA: What do you mean by that? What did you say?

SHRI SURESH PACHOURI: What does he mean by "Gandhi family"? .... *(Interruptions)*

SHRI P. UPENDRA: If you want, I will repeat. .... *(Interruptions)*

SHRI SURESH PACHOURI: We do not want to hear you even.

SHRI S. S. AHLUWALIA: We don't want your repetition.

SHRI P. UPENDRA: Let me repeat what I said. I did not make any charge.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, it should be expunged from the record. It is irrelevant.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : देखिये, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है . . .

श्री एस० एस० अहलुवालिया : ऐसी बात कही है . . . (व्यवधान) ऐसी बात कही है ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अगर उनकी किसी बात को आप गलत साबित करना चाहते हैं तो अपने भाषण में करिये । अपने भाषण में उनकी बात की काट करिये ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Any allegation that is made, has to be authenticated.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): Madam, a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): The Minister is on a point of order. Please sit down. He is raising a point of order. I am allowing him to make a point of order. I am allowing him. Please sit down. Let him raise his point of order. .... *(Interruptions)*

Mr. Ahluwalia, after him I will allow you. .... *(Interruptions)*

What is your point of order?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): I am not concerned with whoever they may be. I am not concerned with persons, but the Rules of this House provide for two things. .... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Please. Let him speak. He is raising a point of order from your party.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Number one, they provide that no allegation can be made without giving previous notice to the Chairman. Number two, they provide that no allegation can be made against a person who cannot defend himself or herself on the floor of the House. On this basis let the debate proceed.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: A point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): What is your point of order? .... *(Interruptions)*

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT): Let us find out. Let us find out.

SHRI V. NARAYANASAMY: You go through the record.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Mrs. Jayanthi Natarajan wants to raise a point of order. .... *(Interruptions)*

श्री सिकन्दर बख्त : उनको बोलने दीजिए, मेहरबानी से उनको बोलने दीजिए ।

شری کلندر بخت : اُن کو بولنے دیجئے
مہربانی سے اُن کو بولنے دیجئے ۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Mr. Narayanasamy, I have allowed her to raise a point of order. Let her raise a point of order.

आप लोग खुद भी नहीं बैठते हैं । आपकी पार्टी से कोई प्रश्न उठा रहे हैं – प्वाइंट आफ आर्डर । मैं एलाउ कर रही हूं । जब आप लोग नहीं बैठेंगे तो कैसे मैं प्वाइंट आफ आर्डर सुनूंगी । आप एक मिनट बैठें । उनका प्वाइंट आफ आर्डर मैं सुनूं ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAHAN: Mr. Upendra, after he recited certain facts about Mr. Quattrocchi, which all of us listened to very quitely, said, because Mr. Quattrocchi was involved and because of his long association which other people might not know about, except what they read from the interested Press, the needle of suspicion points to 10, Janpath. That is totally unacceptable.

SHRI P. UPENDRA: I did not say that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): He did not say that.

SHRI S. S. AHLUWALIA: You said that. .... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): He said that unless it was proved, the needle would be raised.

SHRI S. S. AHLUWALIA: You tell him to withdraw this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): This is what he has said.

SHRI S. S. AHLUWALIA: You tell him to withdraw this. How did he come to this conclusion?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Let Mr. Upendra say what he has to say.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Tell him to withdraw this. ... *(Interruptions)*
This is not the way. How has he made such an irresponsible statement?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): He said, "Unless it is proved, the needle of suspicion will be raised". This is what he has said.

SHRI P. UPENDRA: I will repeat it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Mr. Upendra, what have you said? Let him repeat what he has said.

SHRI P. UPENDRA: Madam, I will repeat. *(Interruptions)* I will repeat. *(Interruptions)* I will repeat what I said. If it is against rules, you can expunge that. *(Interruptions)*

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सरोज जी, आप अपनी सीट पर वापिस जाइये । इतनी उत्तेजना का कोई प्रश्न नहीं है । आप अपनी सीट पर वापिस जाइये । ... **(व्यवधान)** एक मिनट आप बैठ जाइये ।
I say, Saroj Ji, go to your seat.

SHRI V. NARAYANASAMY: It is a very sentimental issue. *(Interruptions)*

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, यह शब्द रिकार्ड से निकाल दिये जाने चाहिएं । ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : एक मिनट । आपके मंत्री जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, मुझे उसका जवाब देने दीजिए । ... **(व्यवधान)** अहलुवालिया जी, आप बैठ जाइये ।

SHRI P. UPENDRA: Madam, I will repeat what I said.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Don't repeat.

SHRI P. UPENDRA: Madam, I will repeat what I said.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं कहती हूं, आप बैठ जाइये । ... **(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे : ऐसी भी क्या बात है ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया । उसमें उन्होंने दो बातें कहीं कि एक तो वह व्यक्ति जो सदन में नहीं होता, उसके खिलाफ आप कोई बात नहीं कह सकते, क्योंकि डिफेंड करने के लिए वह व्यक्ति मौजूद नहीं है ।

दूसरी बात उन्होंने यह कही – दूसरी बात आपने कही ....

SHRI EDUARDO FALEIRO: Whether the person is present or not without previous notice to the Chair...

---

†[ ] Translation in Arabic Script

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : . . . कि अगर आप एलीगेशन लगाना चाहते हैं, तो प्रायर नोटिस चाहिए । यह दोनों बातें नजा हैं और नियम के तहत हैं । मैं रिकार्ड दिखवा लूंगी और इन दोनों की परिधि में अगर यह बात आती है, तो निश्चित यह निकाल दिया जाएगा । अब आप अपनी बात कनक्लूड करिए, उपेन्दजी । . . . **(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे : उपेन्दजी ने जो कहा है . . . **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उसको रिपीट नहीं करें । . . . **(व्यवधान)**

SHRI P. UPENDRA: I will not repeat. .... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): He will not repeat.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : वे रिपीट नहीं करेंगे । यह जो दो नियम हैं, इनकी परिधि में रिकार्ड दिखवा लिया जाएगा । . . . **(व्यवधान)** जोशी जी आप बैठिये । . . . **(व्यवधान)** इतना उत्तेजित मत होइये । वे रिपीट नहीं करेंगे, यह जो दो नियम हैं, इनकी परिधि में रिकार्ड दिखवा लिया जाएगा । चलिये अब आप कनक्लूड करिए । आपका टाईम खत्म हो रहा है, उपेन्दजी ।

SHRI P. UPENDRA: I am finishing in two minutes. Therefore, in the present context, I would suggest certain measures to be taken by the Government. Whatever official papers are available and whatever information is available particularly with the CBI, they must be shared with the nation. A special emissary of the Government of India should be sent to Switzerland to further conduct the investigations etc. Also an inquiry should be made into the Jubilee Finance and the Government should immediately take steps for prompt extradition of Win Chadha. He should be asked to explain the Svenska accounts. Bofors should be asked to give all the details. In this connection I would like to refer to the letter written by the new management of Bofors on June 3. They have written a letter to the Government that "the previous management had done so many things and we are ready to co-operate with the Government now. Please conduct negotiations with us." The Government has not so far replied to the Bofors President's letter which they received on June 3. They should immediately react to them and conduct correspondence with Bofors again. The accounts of the Hindujas viz. Lotus, Tulip and Mont Blanc should be accounted for and the Hindujas should be charged. As I said Mr. Quattrocchi's role should be investigated fully and we must find out what was the reason for his involvement in that. The Government should claim all the amounts seized by the accounts. These amounts should be brought back to the country. Finally, I suggest that the CBI can conduct its own investigations. They have got the new Director who is supposed to be very upright in his career. I hope that something better would emerge from the CBI investigation.

In addition I suggest a new Joint Parliamentary Committee be appointed in view of the revelations we have got so that this investigation can go on further and this issue can be closed once and for all. (Ends).

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, बड़े अफसोस की बात है कि यह सदन आज फिर उसी बोफोर्स के बारे में चर्चा करने के लिए चला है जिसके काले बादल भारत के वायुमण्डल पर कितने साल से मंडरा रहे हैं और कितनी बार विधात इस देश के लोगों को किया है । जहां तक मुझे याद है दोनों सदनों में करीब 50 से भी ज्यादा बार बोफोर्स पर चर्चा हो चुकी है और करीब एक सौ से भी ज्यादा घंटे, इस सदन का बहुमूल्य समय इस बोफोर्स कांड के ऊपर चर्चा करने में लगा है, पर हर बार हम वही भूल करते हैं ।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, I wish to draw your attention to a procedural aspect. To the best of my recollection, we all agree to have a discussion under Calling Attention motion. Now it has been taken up as a Short-Duration Discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): It has been listed as a Short-Duration Discussion.

SHRI S. JAIPAL REDDY: True, but to the best of my recollection, earlier we had insisted upon a *suo motu* statement by the Government. Then, we were told that under the Calling Attention motion also Government would give an official statement. Under a Short-Duration Discussion we will not have the benefit of any statement by the Government.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : ऐसा है, जयपाल रेड्डी जी आप बहुत लेट इस प्रश्न को उठा रहे हैं । शार्ट इयूरेशन डिसकशन आज सुबह से बिज़नैस में लिस्टेड था । अगर आप चाहते तो सुबह उठाते, अब तो चर्चा शुरू भी हो चुकी है ।

Now it is too late.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I plead guilty.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): But this delay can't be condoned by me.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I expect the Government to make up for this lapse or confusion.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : जहां तक मुझे जानकारी है शायद मारग्रेट जी जवाब देने वाली हैं ।

SHRI S. JAIPAL REDDY: That statement will be made by the Government.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : पूरी डिबेट का जवाब मारग्रेट जी देने वाली हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जवाब नहीं, official statement.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : जब आफिशियल स्टेटमेंट लगर कालिंग अटेंशन के तौर पर चाहते थे तो सुबह जब यह लिस्ट हुआ था तब आपको उठाना चाहिए था, अब चर्चा के मध्य तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती ।

Therefore, your application for condonation of delay stands rejected.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : महोदया, जैसा कि मैं कह रहा था कई वर्षों से अर्थात् 17 अप्रैल 1987 को पहली बार यह स्वीडन रेडियो की आवाज़ के माध्यम से पता चला कि बोफोर्स की डील में कुछ घोटाला हुआ है । तब से आज तक यह एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है । संसदीय प्रणाली के हिसाब से जो-जो रास्ते अपनाने चाहिए थे इस प्रश्न चिन्ह को मिटाने के संसदीय प्रणाली के माध्यम से वह सारे रास्ते अपनाए गए और सारे रास्तों पर चला गया, पर कुछ लोगों के दिमाग का प्रश्न चिन्ह अभी तक नहीं मिटा । आज तक यह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और हर वक्त यह जब भी इनके दिमाग में आता है कि कांग्रेस सशक्त हो रही है तो उस वक्त यह आवाज़ उठाने लगते हैं । 1989 का चुनाव . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : गौतम जी, बीच में व्यवधान न करें, चर्चा को चलने दें ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा । भारत की जनता ने कुछ क्षण के लिए इन पर विश्वास भी किया । विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पटना के गांधी मैदान में खड़े होकर अपनी जेब से कागज का पुर्जा निकाला और कहा कि यह मेरे पास राजीव गांधी के स्विस एकाउंट का नंबर है । मैं राजसत्ता हासिल करने के 15 दिन के अंदर यह सब बताऊंगा और गिरफ्तार करूंगा, पर राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने के बाद ही वह पुर्जा शायद उनकी पॉकेट से गिर गया और वह कागज मिला ही नहीं ।

श्री रामेश्वर कुमार यादव "रवि" (बिहार) : आप उस मीटिंग में थे, जब वी० पी० सिंह गांधी मैदान में भाषण कर रहे थे ?

श्री एस० एस० अहलुवालिया : मैं था, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हर पार्टी की मीटिंग अटेंड करता हूं ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : यह जासूस है ।

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Only police spies attend the meetings of all the parties.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : वह जयपाल रेड्डी जी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे पास इंफार्मेशन का खजाना कहां से आता है । मैं सब की बात सुनता हूं और सब की बात का जवाब देता हूं ।

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : आप डा० स्वामी तो नहीं हैं ?

श्री एस० एस० अहलुवालिया : मैं डा० स्वामी नहीं हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : दिग्विजित पृथ्वीजित सिंह को जगाइए, वह सो रहे हैं सदन में ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : उनकी तबियत खराब है, क्यरल फीवर से पीड़ित हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : ठीक है, आप बोलिए ।

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Madam, under the rules, sleeping is allowed, only snoring is not allowed.

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): Madam, I have 101°F of temperature. I am still here because I have tons to speak on Bofors. I am waiting for my turn. Once my turn is over, I will go to the hospital. *(Interruption)*

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप घर जाकर आराम कीजिए या अहलुवालिया जी बैठ जाएं तो मैं आपको बुलवा देती हूं ।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: No. I will not speak first. I will follow the dictates of my party as a disciplined soldier.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : ठीक है, बोलिए अहलुवालिया जी ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, that was not necessary. It was very unfair to him.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : मैं जब बीच में कुछ कह रहा था तो मैंने सोचा कि आप शांतिपूर्ण ढंग से डिबेट चलाना चाहती हैं, पर जब आपने डिबेट में इंटरफियर करना शुरू कर दिया . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैंने कहां इंटरफियर किया, मैंने तो कहा कि वह जाएं और आपकी बात सुनें।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदया, यह शुरूआत गांधी मैदान से होती है और आज यहां तक पहुंची है और जैसाकि मैं बता चुका हूं 50 से भी ज्यादा बार राज्यसभा और लोकसभा में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और 100 से भी ज्यादा घंटे का समय हम इस पर खर्च कर चुके हैं। महोदया, बिहार के सूखा पीड़ित लोगों के बारे में चर्चा करने के लिए जब हम समय मांगते हैं, तब शायद संसद के पास समय की कमी होती है या गरीब लोगों के यहां पानी कैसे पहुंचेगा, सड़क कैसे पहुंचेगी, उस बारे में जब चर्चा का वक्त मांगा जाता है तो समय कम हो जाता है। कभी किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और जब मिनिस्टर का स्टेटमेंट होता है तो उस पर क्लैरीफिकेशंज के लिए समय की कमी हो जाती है, लेकिन इस चर्चा में सौ से भी ज्यादा घंटे लगाए गए हैं और आखिर हम पहुंचे कहां हैं?

महोदया, इसे चुनावी मुद्दा बनाकर बी०जे०पी० ने तोप की गाड़िया बना दीं और उसे लेकर गांव-गांव घूमे जहां कि लोगों को पता ही नहीं था कि बोफोर्स क्या होता है, लोगों को उसकी कैपेसिटी का पता नहीं था, उन्होंने कभी बोफोर्स तोप देखी नहीं थी, पर मुझे याद है कि हमारे इसी सदन के सदस्य जोकि जे०पी०सी० के मेंबर थे और जिनका कि आर्मी का बैकग्राउंड है, उन्होंने बोफोर्स तोप के बारे में कहा था कि —

"It is one of the best guns in the world."

यह उनका रिमार्क है और जसवन्त सिंह जी सौभाग्य से बी०जे०पी० के सदस्य हैं। यह रिमार्क उनका था, मैंने उनके मुंह में यह सब नहीं डाला था और जे०पी०सी० के रिपोर्ट देते वक्त उन्होंने कोई अलग नोट नहीं दिया था कि उन्होंने रिपोर्ट के साथ सहमति व्यक्त नहीं की अर्थात् वह रिपोर्ट के साथ पूरी तरह सहमत थे।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Jaswant Singh?

SHRI S. S. AHLUWALIA: Yes.

SHRI KAMAL MORARKA: Madam, may I correct Mr. Ahluwalia?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Jaswant Singh was not on the JPC.

SHRI KAMAL MORARKA: Madam, do I have your permission to correct him?

4.00 P.M.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : जसवंत सिंह जी डिफेन्स कमेटी के दौरे पर गए थे। जब वहां बोफोर्स गन चलाई गई तो गन चलाने के बाद उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट यह दिया, जो सारे अखबारों में, सारी मैगजीनों में छपा था। यह चीजें आज तथ्य के रूप में सामने हैं। आज हम फिर 1993 में खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ घोटाला हुआ था? अरे, क्या घोटाला हुआ था? फेडरल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट को पढ़ा जाए कि उसमें क्या लिखा है? मैं जानना चाहता हूं, क्या लिखा है? हो सकता है कि मुझे स्विस बैंक के बारे में कम पता हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि स्विस बैंक में जो पैसा रखता है, चाहे वह हिन्दुजा हों, चाहे क्वात्रोची हों या और कोई एक्स, वाई, जेड हों वह क्यों रखते हो? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है सीक्रेसी। वह सीक्रेसी मेन्टेन करना चाहते हैं इसलिए रखते हैं। इन लोगों ने यह जो अपील की है, अपील करने का मतलब यह कैसे साबित होता है कि यह लोग दोषी हैं या इन लोगों ने उसमें कमीशन लिया है। यह तो हुआ कि एक आदमी, मैंने चोरी नहीं की, मेरे घर पुलिस आ रही है, पुलिस मेरा घर सर्च करना चाहती है, मेरे घर में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, जिनको मैं नहीं दिखाना चाहता दुनियां को। मेरे घर में पड़ी हुई हैं चीजें, मैं नहीं दिखाना चाहता। लोग कहते हैं कि सुन्दरता और धन दोनों छुपा कर रखने की चीजें हैं। यह गांव के बड़े-बड़े कहते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। मैं नहीं दिखाना चाहता अपना एकाउण्ट, आप मेरा एकाउण्ट क्यों देखेंगे? मैंने एक ऐसे बैंक में एकाउण्ट रखा है, जहां किसी को अधिकार नहीं है उसको पूछने का कि यह एकाउण्ट कहां से आया या पैसा कहां से आया।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जी० नारायणसामी) पीठासीन हुए।]

मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर आप मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। मेरे एकाउण्ट की पूरी खोजबीन करना चाहते हैं। क्या मेरे को इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं इसको रोकूं या किसी कचहरी से अधिकार लूं कि क्यों आप मेरे यहां सर्च कर रहे हो?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ यही जानना चाहूंगा, यह जो सात लोग हैं इन सात लोगों के खिलाफ जो बैकग्राउण्ड है, सी० बी० आई० के पास सबकी बैकग्राउण्ड है, हरेक आदमी की बैकग्राउण्ड के बारे में क्या कहना चाहती है सी० बी० आई०? क्या उनके पास कोई प्राइमाफेसी केस है इन सातों के खिलाफ? लगा है, तो क्यों नहीं कार्यवाही की गई? क्यों बार-बार इस सदन का वक्त लिया जाता है? क्यों नहीं एक बार फैसला होता इसका? यह सोचने की बात है।

महोदय, आपने पीछे पढ़ा होगा कि अजिताभ बच्चन के खिलाफ बोफोर्स के मामले में किसी ने लिख डाला एक लेख और अजिताभ बच्चन ने लंदन कोर्ट में उसके खिलाफ मानहानि का केस किया। वह केस जीत गए और हरजाना भरना पड़ा उस अखबार वाले को क्योंकि वह सबस्टेंसिएट नहीं कर सका। आज तक लंदन का अखबार सबस्टेंसिएट नहीं कर सकता है। अभी हमारे मित्र उपेन्द्र जी बड़ी तारीफ कर रहे थे "हिन्दु" की, बड़ी तारीफ कर रहे थे "इंडियन एक्सप्रेस" की, बड़ी तारीफ कर

रहे थे चित्रा सुब्रह्मण्यम की, बड़ी तारीफ और लोगों की कर रहे थे । आप तारीफ करते हैं, अच्छी बात है, आपका नाम अखबार में छपता है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह अखबार भी क्या है । यह अखबार व्यापार है और यह प्रेशर ग्रुप है । आखिर लड़ाई किसकी है ? दो बिचौलियों की लड़ाई है । दो बिचौलियों की लड़ाई और रणक्षेत्र भारत भूमि, रणक्षेत्र भारतीय सरकार, रणक्षेत्र यह टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी । दो बिचौलिए लड़ रहे हैं, एक बंदूक नहीं बेच सका, एक ने बेच डाली । लड़ाई इन दोनों की है और उसके बीच में सिपाही बने हम झूठमूठ । कोई किसी का सिपहसलार बन गया है, कोई किसी का लेफ्टिनेंट बन गया है । हम यह नहीं सोचते कि हम अनजाने में, जाने में किसी के दलाल बनते जा रहे हैं, किसी की दलाली कर रहे हैं । चाहे वह आस्ट्रेलियन गन हो या स्वीडन की गन हो, हम किसी की दलाली करना चाहते हैं । अगर हमें दलाली करनी है तो मातृभूमि की करें, भारतमाता की करें । यहां रोज-रोज इस तरह के सवाल उठाकर हम गरीबों की मांगों का समय छीनकर ऐसे फिजूल कामों में लगाते हैं । पर हमने क्या किया है ? हम प्रेशर ग्रुप में पड़ते हैं । आज भारतवर्ष के गणतांत्रिक अधिकारों में सबसे बड़ा प्रेशर आता है मीडिया का । यह मीडिया कौन कंट्रोल कर रहा है ? कितने मीडिया के अखबार हैं जो कि जर्नलिस्ट चलाता हों, जो गर्व से कह सके "तिलक" की तरह कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ? यह तो पेशेवर मीडिया का एक प्रेशर ग्रुप बना हुआ है और उसी तरह आज इंडस्ट्रियल हाउसिस हैं । बाईं तरफ से प्रेशर नहीं होता है तो दाईं तरफ से डाल देते हैं, दाईं तरफ से नहीं होता है तो ऊपर से देते हैं, बिचौलियों को बीच में डाला है । आज दिन-प्रतिदिन इस सदन के एजेंडे का भी बिजनेस एडवाइज़री कमेटी फैसला नहीं करती है, इस सदन के एजेंडे का फैसला भी हमारे अखबार करते हैं । प्रेस क्लब में बैठकर एक एडीटर बोल देता है रात में कि लोक सभा का एजेंडा कल क्या होगा, राज्य सभा का क्या होगा और वही होता है । हम सब कुसूरवार हैं और यही कारण है कि हम भोग रहे हैं । सौ से भी ज्यादा घंटे हमने बर्बाद किए हैं इस चर्चा में और आज भी जो हमने चर्चा आरम्भ की है, उसका तथ्य क्या है ? कोर्ट ने क्या लिखा है ? कोर्ट से क्या बाहर आया है ? कोर्ट ने क्या प्रमाणित किया है कि ये सातों आदमी बिचौलिए थे या इन्होंने कमीशन लिया है ? कहां प्रमाण है इसका ? महोदय, मैं जानना चाहूंगा, हिन्दूजा का नाम जब आया, हमारे आदरणीय मित्र हैं — राम जेठमलानी जी, रोज़ प्रश्न करते थे, 20 प्रश्न, राजीव गांधी से बोफोर्स पर, पर जिस दिन पता लगा कि हिन्दुजा इन्वाल्व हैं, सांप सूंघ गया । उसी दिन सांप सूंघ गया, लिखना बंद कर दिया ।

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदय, यह एतीगेशन है ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : अरे भाई, आपको वकालत करने की जरूरत नहीं है, बहुत नामी वकील हैं, बड़ा नाम है इनका । और, मैं खुद भी वकील हूं । घबराने की जरूरत नहीं, मैं सलाह ले लूंगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Don't answer the interruptions. You can speak.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपने मेनिफेस्टो के ऊपर, सुप्रीम मेनिफेस्टो बोफोर्स को रखा था और मुझे जहां तक मालूम है कि पद ग्रहण करने के पहले ही उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, बड़ी लम्बी-चौड़ी लिस्ट थी । पता नहीं कहां-कहां से नाम ले आए, किस-किस के रिश्तेदारों का, किसी के फादर इन लॉ का, किसी के ब्रदर इन लॉ का, किसी के भाई का और बड़ी लम्बी लिस्ट भेजी गई थी सी० बी० आई० के पास । सी० बी० आई० ने उनके रहते-रहते, वह प्रधान मंत्री के पद पर थे, उसी वक्त आयद सी० बी० आई० ने उसकी रिपोर्ट लाकर पेश कर दी थी । उस रिपोर्ट में क्या था ? क्या सच्ची थी, झूठी थी ? आज फिर हमने सात नाम लेकर घूमना शुरू कर दिया है । ये सात नाम कौन हैं ? मैं यही जानना चाहता हूं और सारा देश जानना चाहता है कि आखिर 22 जुलाई, 1993 को फेडरल कोर्ट ने क्या नई बात कह दी है ? कौन-सी नई चीज उद्धृत की है जिसके माध्यम से पता लगता है कि पता नहीं भारत के किस-किस परिवार ने और किन-किन लोगों ने कितना-कितना पैसा ले लिया ? यह सिर्फ आया है कि ये सात आदमी कचहरी में, कोर्ट में अपनी हिफाज़त करने के लिए, अपने बैंक अकाउंट की रक्षा करने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे थे । हो सकता है उनमें से कुछ, दो-एक, ऐसे हों जिनके कहीं अकाउंट हों या उनके हैडिंग में कहीं नाम हों, पर सातों के नाम को लेकर हंगामा और पार्लियामेंट में चर्चा सारे विषयों को छोड़कर ? कल तक तो आप देश की आर्थिक नीति, देश की गरीबी, देश की बेकारी और देश के बारे में बहुत चिंतित थे । पर, पता नहीं आज सारी चीजों को छोड़कर गंदी कब में भी क्या निकालकर लाना चाहते हैं ? मैं जानना चाहूंगा कि आप मंत्री महोदया बताएं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, इस फेडरल कोर्ट की जजमेंट में क्या लिखा है और मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस फेडरल कोर्ट की जजमेंट में इंडियन प्रेस के बारे में भी कुछ लिखा है, इंडियन जर्नलिस्ट के बारे में कुछ लिखा है ? अगर लिखा है तो उसको भी उद्धृत कीजिए, क्योंकि समय से पहले हर चीज जो यहां पर आधी पकी-पकाई चीजें हमारे सामने रखकर उसका जो मज़ाक उड़ाया जाता है, उसका भी जरा पता चले कि फेडरल कोर्ट के सामने कैसी बेइज्जती होती है हमारे पत्रकारों की, जो बड़े गर्व से छाती फुला-फुलाकर यहां घूमते हैं । अमिताभ बच्चन के केस में क्या कारण था ? उसका कौन सा फ्लैट है, कहां खरीदा, बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, सब कुछ चर्चा तो कर चुके हैं यहां पर और उसके बाद लन्दन कोर्ट में केस हारा गया । वे डिफेमेशन सूट में हारे, पत्रकारों ने हाथ जोड़े और बाद में हरजाना भरा, उसको भी जरा बताइए इस सदन के माध्यम से ताकि इस देश की जनता को पता चले कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है ? महोदय, जहां तक पता है हिन्दूजा की मूवमेंट पर वाच करने के लिए सी० बी० आई० ने एक निर्देश जारी किया था । उसको फोनोलाप करने का

निर्देश जारी किया गया था । यह निर्देश किस वक्त रद्द किया गया, किस प्रधान मंत्री के काल में यह रद्द हुआ और क्यों हुआ, उसके पीछे किसका हाथ था, यह भी जरा सदन को बताने की कृपा करें ? (समय की घंटी)-

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सी० बी० आई० के पास मि० कोटरोची के बारे में क्या रिपोर्ट है, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह कौन है । मैंने अखबार में इनका कंट्राडिक्शन पढ़ा है । मैं पढ़कर यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह आदमी जो कंट्राडिक्शन दे रहा है, आपकी सी० आई० आई० इसके बारे में क्या कहती है ? क्या आपके पास में इसके प्रति संदेह होने के कारण हैं ? यह एक विदेशी है, हिन्दुस्तान में रहता है और कुछ कम्पनियों का काम देखता है और जिन कम्पनियों का यह काम देखता है वह आर्म्स में डील नहीं करती हैं । उसके पीछे क्या आरोप हैं और अगर कोई आरोप हैं, कोई संदेहास्पद चरित्र का आदमी है तो आज तक तीन सरकारें आई गईं, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है ? यह फाईल वी० पी० सिंह ने भी देखी है, चन्द्रशेखर ने भी देखी है और नरसिंह राव जी भी देख रहे हैं । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिर सी० बी० आई० ने इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन दी हैं, यह बताने की कृपा करें ?

महोदय, आज हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे, जबकि मैं जहां तक जानता हूं कि अखबारों के माध्यम से पता लगा है कि फेडरल कोर्ट ने अभी सिर्फ एक नाम डिस्क्लोज किया है और जो फाइनल आर्डर है और डौक्यूमेंट्स वगैरह हैं, यह वहां की केबेकेशन खत्म होने के बाद आएंगे । तो जिसने अपील की है सिर्फ उसी का नाम है । किन्तु उस पर चर्चा करके हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं और शायद फिर हम एक सौ घंटे की नई तैयारी कर रहे हैं, एक नया दौर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सारे दौर हमारे पूरे हो गए हैं, दूसरे कारतूस चल चुके हैं और कोई नया कारतूस तैयार कर रहे हैं । हमें यह बताने की कृपा करें कि फेडरल कोर्ट ने कब लास्ट डेट दी है, कब वह एकाउंट्स के बारे में फाइनल रिपोर्ट भारत सरकार के सी० बी० आई० को या भारत सरकार को सौंप देगी, मैं यही जानना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्री जगदीश प्रसाद अवस्थी (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन, मैं बड़े ध्यान से कांग्रेस के प्रवक्ता अहलुवालिया जी को सुनता रहा । उन्होंने दुःख व्यक्त किया कि सैकड़ों घंटे यहां बहस में खराब हो गए, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला । मैं उनकी बात से सहमत हूं कि यहां पर सैकड़ों घंटे बहस में लगे लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला । परन्तु सवाल यह है कि क्यों नहीं निकला ?

दूसरा, उन्होंने कहा कि शायद दो कंपनियां हैं जो आपस में लड़ रही हैं और उसमें हम लोग दलाल बने हुए हैं । मुझे बड़ा दुःख है कि उन्होंने यह बात कही, यह हरगिज नहीं है और न होना चाहिए ! तीसरी बात उन्होंने यह कही कि यह केवल मीडिया के द्वारा खड़ा किया गया सवाल है । ठीक है, मीडिया का इसमें रोल है, गलती भी करते हैं, सही भी करते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार जो-जो मीडिया में छपता रहा है या छप रहा है, उसका समाधान कर सकी है या नहीं कर सकी है । मेरा मानना है कि नहीं कर सकी है । मैं बड़े दुःख के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या हमें अब न्याय की ओर बढ़ने के लिए विदेशी न्यायालयों का सहारा लेना पड़ेगा ?

स्वीडन की अदालत ने कुछ नामों का उल्लेख किया है । क्या हमें ये नाम मालूम नहीं थे और मैं कहता हूं कि अगर मालूम नहीं थे तो भारत सरकार और सी० बी० आई० किस मर्ज की दवा है ? मैं यहां बड़ी शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हूं और मुझे यह कहना पड़ रहा है कि 5 व्यक्तियों और 2 कंपनियों के नाम स्विस कोर्ट ने हमारे सामने रखे हैं और हम इंतजार में हैं कि आफिशियली वह हमें नाम दें । क्या हम अपने देश में उससे संबंधित व्यक्तियों पर, जिन पर संदेह है कि उन्होंने दलाली खाई है, गैर-कानूनी काम किया है, क्या हमारे पास ऐसे साधन नहीं हैं कि हम उनको पकड़ सकें ? क्या हमारे पास अदालतें नहीं हैं जो फैसला कर सकें ? लगता तो यही है । परन्तु मैं यह कहूंगा कि अदालतें तो हमारे पास हैं । एजेंसीज हमारे पास हैं लेकिन उन एजेंसियों को, अदालतों को सरकार काम नहीं करने देती ।

आज हमारे मित्र यहां प्रसन्न बैठे हैं, होना भी चाहिए क्योंकि कल 14 वोटों से सरकार बच गई । अच्छ क्यों गई, सब जानते हैं लेनदेन की वजह से बच गई । एक और आरोप इस सरकार पर सिद्ध हो गया कि यह भ्रष्टाचार के आधार पर चल रही है । उन दिनों जब 1986 के अंदर बोफोर्स का मामला उठा और आज जब दोबारा उठ रहा है तो दृश्य वही दिखाई देता है जो उस समय था । आज की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं । दुःख की बात है कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी किसी आदमी ने आरोप लगा दिए हैं लेकिन आखिरकार इन तथ्यों को रोकने के लिए कौन लगा है—सी० बी० आई० । बोफोर्स के तथ्यों को रोकने में कौन लगा था—सी० बी० आई० । किसने रोका ? दिल्ली की अदालत में सालों तक पड़ा रहा, उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया । आखिर क्यों ? किसने किया ये ? आपने किया, इस सरकार ने किया । दुःख की बात है कि विदेशी अदालत फैसला करके हमारे पास नाम देती है और हमारी दिल्ली की अदालत उस तरफ बढ़ने में रूकावट डालती है । कौन रूकावट डालता है, क्यों डालते हैं ? आप रूकावट डालते हैं, सरकार डलवाती है । आज हिन्दुजा या उसके साथी अदालत के सामने मुजरिम हैं लेकिन देश के सामने मुजरिम ये कम हैं सरकार ज्यादा है । They are criminals. क्योंकि आपने क्रिमिनल्स को सामने आने से रोका । एक बार नहीं बार-बार रोका । मैं पूछना चाहता हूं कि ये 5 नाम कौन नहीं जानता ? सब जानते हैं । कोटरोची, गोपालचन्द, हिन्दुजा, प्रकाश हिन्दुजा, आर० एस० एस० हिन्दुजा, श्रीचंद हिन्दुजा और दो जुबली फाइनेंस .....(व्यवधान)..... दुनिया में नाम इनके बार-बार आ रहे थे ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Who attended their Diwali party in 1991 ?

SHRI SURESH PACHOURI: Who attended the Hindujas' Diwali Party?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं जानता हूं ये आदतें हैं और ये .....**(व्यवधान)**.....

श्रीमती जयन्ती नटराजन : आप जवाब दीजिए .....**(व्यवधान)**.....

कुमारी सरोज खापर्डे : उनका नमक खाते हो तो उनका जवाब दीजिए कम से कम .....**(व्यवधान)**.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : ये मेरा समय खराब कर रहे हैं बेकार .....**(व्यवधान)**..... ये मेरे खाते में नहीं जाएगा . . .

कुमारी सरोज खापर्डे : कम से कम उनका नाम कोट होना चाहिए, इसमें शर्म की क्या बात है .....**(व्यवधान)**.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं जानता हूं दो बड़ी अच्छी सुंदर महिलाएं हैं .....**(व्यवधान)**.....

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Your leader also claimed that they were great sons of India .....*(Interruptions)*.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अच्छी महिलाओं की बात नहीं कहता .....**(व्यवधान)**.....

कुमारी सरोज खापर्डे : आप बैचलर हैं, आपको महिलाओं की बात नहीं करनी चाहिए .....**(व्यवधान)**.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इसीलिए मुझे अनुभव नहीं है । इसीलिए मैं दो चार मिनट गम खा गया । सवाल यह नहीं है कि .....**(व्यवधान)**.....

SHRIMATI JAYANTHI NATRAJAN: It is better that the BJP Members do not talk about Hindujas .....*(Interruptions)*....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : खापर्डे जी आप भी मेरी श्रेणी में हैं, आप बोलिए मत . . . **(व्यवधान)** . . .

कुमारी सरोज खापर्डे : इसीलिए मैंने कहा दो सुंदर महिलाओं के बीच में गड़ा मत डालिए . . . **(व्यवधान)** . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Mathur, you please come to the subject. Don't answer them .....*(Interruptions)*..... I will reduce your time .....*(Interruptions)*.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपकी इन कंपनियों के पिटको, संगम, टूरिस्ट, माउंटबेटन आज यह कौन नहीं जानता था सब जानते थे । मैं पूछना चाहूंगा कि जिन चड्ढा के जो पासपोर्ट पर रोक लगाई गई थी उसको किसने हटाया, क्यों हटाया ? हिन्दुजा के ऊपर कार्यवाही आज तक क्यों नहीं की गई ? मैं नहीं जानता उस समय कौन था, बैठे होंगे राजीव जी, चाहे चन्द्रशेखर जी बैठे हों और चाहे बैठे हों, मुझे बहुत अच्छा नाम नहीं लगता वी० पी० सिंह जी, कोई बैठा हो, मैं नहीं जानता । लेकिन तीनों सरकारें बहुत बड़ी मुजरिम हैं । लेकिन इसके साथ ही मेरे मित्र ने कहा कि वी० पी० सिंह जी ने ऐलान किया था । वह चिट्ठी उनकी खो गई । मैं नहीं जानता कि चिट्ठी थी, खो गई या नहीं, लेकिन वह नाम नहीं बता सके । सवाल यह है कि आपने वी० पी० सिंह के बीच में भी लड़ाई लगाने की कोशिश नहीं की ? इसलिए कि आप अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे ? बहुत बड़े-बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हैं ।

पहला सवाल है कि 1986 के अंदर यह सौदा किया गया है । लेकिन आपने यहां कहा कि मार्च में और सरकार ने रिकार्ड दिखाया कि यह वाईडिंग चार्जेज जनवरी में किए गए । मैं पूछना चाहता हूं कि सौदा तो होता है मार्च में, वाईडिंग चार्जेज जनवरी में तय हो गए ? इसका मतलब यह है कि घपला उस दिन शुरू हुआ जिस दिन रेडियो ने ऐलान किया । घपला आपने पहले ही शुरू कर दिया क्योंकि आप गिल्टी थे । आप ईमानदार नहीं थे, घपले में शामिल थे । दूसरे सी० बी० आई० ने बार-बार यह कोशिश क्यों की यह कहने की कि यह क्रिमिनल ऐक्ट नहीं है, यह फेरा का है, करेंसी का है । क्योंकि स्विस कोर्ट का कानून है कि यदि यह साबित हो जाए यह क्रिमिनल ऐक्ट है तो उस पर कार्रवाई करेंगे । आखिरकार सी० बी० आई से आपने क्यों नहीं कहा या सी० बी० आई० ने यह क्यों नहीं कहा कि इसमें क्रिमिनल ऐक्ट है । क्योंकि आप जानते थे कि दाढ़ी में तिनका है । आप चोर हैं । इसलिए आपने उनको कहने नहीं दिया ।

कुमारी सरोज खापर्डे : चोर किस को बताया ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उस समय की सरकार को । आज भी है यह दूसरी बात है । भेद खुलना शुरू हो गया 1987 में । लेकिन एफ० आई० आर० दाखिल नहीं की 1990 तक । 1987 में भेद खुलना शुरू होते ही 1990 में आप एफ० आई० आर० दर्ज करते हैं । इतनी देर किसलिए ? क्योंकि आप जानते थे । लेकिन जिस समय पब्लिक का प्रेशर बना तब आपने दिखाने के लिए एक एफ० आई० आर० दाखिल कर दिया । क्योंकि आप घंटी बजा देंगे इसलिए मैं थोड़े से नाजुक सवाल पर आता हूं आप जरा दिल संभाल कर बैठिये । शोर मचाने की तैयारी किजिए । क्योंकि मैं जानता हूं आप जरूर मचायेंगे । नहीं मचायेंगे तो मैं आपको दाद दूंगा । जो बात आगे मैं कहने वाला हूं वह यह है कि मेरे मित्र ने एक बात उठाई थी कि क्वेटरोची महोदय का गन के लेने-देने में कोई संबंध नहीं । बहुत

सच कहा अहलूवालिया जी ने । मैं पूछता हूं जिसका जिस मामले से कोई संबंध नहीं है वह अदालत में क्यों जाता है । मैं नहीं कहता वह चोर है । मैं उदाहरण दे रहा हूं । कोई चोर हो वह अदालत में जाकर कहता है मैंने चोरी नहीं की मेरा नाम मत लीजिए, इसका क्या मतलब । कोटरेची जिसने चोरी नहीं की वह अदालत में क्यों गया और कहा कि नाम न दीजिए । चोर की दाढ़ी में तिनका । क्योंकि वह जानते थे कि मेरा नाम है । आज आने वालों ने भी आरोप लगाया पत्रकारों पर । वह कहते हैं बिगाड़ते हैं मामले को । वह बिगाड़ते नहीं हैं कई बार सुधार देते हैं । आज भी आपकी सी० बी० आई० ने बजाय इसके कि इसकी क्या असलियत है यह बताते, यह लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि आपने पहले लीकेज क्यों किया । लीकेज क्यों किया इसलिए कि आप लीपा-पोती न करें । पत्रकारों को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने फाइलें खोल कर आपके हाथ बांध दिये हैं ताकि आप चोरी न कर सकें ।

आप जो बात कहने वाले हैं उसके लिए जरा दिल थाम कर बैठिये । जो चीफ है बोफोर्स का मार्टिन आरडियो उन्होंने इसमें लिखा है क्यू और आर । क्यू के बारे में कहते हैं—Q's involvement was a problem because of his closeness to R. क्यू तो कोटरेची से खत्म हो गया और अब आर कौन है ? .....(व्यवधान)..... मिंत्रों अब शोर मत मचाओ ।

कुमारी सरोज खापर्डे : आर जो आपने कहा वह उधर बैठे हैं, राम जेठमलानी । .....(व्यवधान).....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप कह सकते हैं आर से राम जेठमलानी, रामकृष्ण हेगड़े, रामदास अग्रवाल, और राजीव गांधी का नाम भी हो सकता है, और कई नाम भी हो सकते हैं । सबका नाम हो सकता है ।

श्री एस० एस० अहलूवालिया : आप तो राम का नाम पढ़िये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैंने कहा था कि कल्पना में सब आ सकता है । राम जेठमलानी आ सकता है, रामदास अग्रवाल आ सकता है और राजीव गांधी भी आ सकता है । सवाल यह है कि राजीव गांधी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि यह बात साबित हो चुकी है कि इटेलियन कनेक्शन है । आपने दो-तीन बातें खड़े हो कर कही कि इसमें रिश्वत नहीं ली गई है, लेकिन वह साबित हो गया है । आपने कहा था कि कोई भारतीय नहीं है, लेकिन वह भी साबित हो गया है । आपने कहा था कि कोई बाहरी आदमी है, वह भी साबित हो गया है और यह भी साबित हो गया है कि आर भी इसमें इंवोल्व है ।

ऐसी स्थिति में अब मैं दो-तीन सुझाव दूंगा । नं० 1 तो रेड अलर्ट डिक्लेयर किया जाना चाहिए जिससे कोई भी आदमी देश से निकल कर भाग न सके चाहे वह क्वात्रोची हो, चाहे हिन्दूजा हों । इन लोगों के कागजात जब्त किये जायें और इनका एक्स्ट्राडिशन मांगा जाय । सी० बी० आई० को इस देश में स्वतंत्र छोड़ा जाय । मैं अपने सी० बी० आई० के नये अधिकारी से अपील करना चाहूंगा कि मित्र, तुम्हारे ऊपर उतनी ही भारी जिम्मेदारी है जितनी भारी जिम्मेदारी प्रधान मंत्री की होती है । देश के प्रति तुम्हारी लायलिटी और जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी राष्ट्रपति की होती है । आप जोखम उठाकर भी सच कहिये । न राजीव गांधी को बचाइये, न नरसिंह राव को बचाइये । आज सी० बी० आई० का काम सिर्फ सरकार के मंत्रियों को बचाना रह गया है । मुझे दुख है कि I say this with all the authority आर को बचाने का काम किया जा रहा है । मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी और शोर तो मचाया, लेकिन कम मचाया । अब आप शोर मचाइये ।

कुमारी सरोज खापर्डे: माथुर साहब, आपके लिए शोर नहीं मचाएंगे तो और किस के लिए मचाएंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपका और हमारा तो रिश्ता पुराना है । इसीलिए आप शोर मचा रही है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, kindly take your seat. Now, Shrimati Jayanthi Natarajan.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: मैं यह कहना चाहता हूं कि .....(व्यवधान).....

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI V. NARAYANASAMY) Mathurji, please sit down.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Thank you very much, Sir, Mathurji was speaking with such tremendous authority that we did not want to interrupt him and we were listening to him with rapt attention. Mathur Saheb just now spoke, very, very authoritatively about various notings in Mr. Martin Ardbo's diary. I am filled with interest to know about what he said and at his superb analysis. Before I even begin my speech, I want to know how did he get the copy of this diary .....*(Interruptions)*..... Let me finish.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I have got it from the press reports.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Yes, the source of all the wisdom and inspiration .....*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NARAYANASAMY): Mr. Mathur, kindly take your seat. You have already spoken.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपकी महिलाओं के प्रति सहानुभूति है, इस बात की मुझे खुशी है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NARAYANASAMY) : But I am not happy. You kindly take your seat. I am not happy.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : I only want to say that it is now proof beyond reasonable about that only newspapers are the source of all the wisdom and inspiration for the Opposition. I don't blame them because they are not only bankrupt of policy, of vision, of basic ethics but also of information and have to depend on Chitra Subramanian.

Sir, I want to ask the Minister a very serious question : Where is this great diary that all the newspapers are writing about? Where are they getting their reports from ? I want to know this from the Minister because first of all the CBI has the diary. Does the CBI have Mr. Martin Ardbo's diary? Where is all this information coming from ? How does the Opposition get all this information ?

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu) : The CBI has failed in its duty.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : Having said this, I want to start by saying that I also endorse most wholeheartedly all the other aspects about which Mr. Mathur has said. Very many important points were made by Mr. Mathur. The most important point is that not enough effort went into pursuing the matter or finding out the truth in the Bofors matter. I agree with him most wholeheartedly. But the person who failed most visibly in this matter was Mr. V. P. Singh, the same V. P. Singh, whose Government was propped up by the BJP, on the one hand, and the Left, on the other hand.

Before I say anything further, I want to add that any meaningful efforts that were taken by the Government of Rajiv Gandhi and, now, by the Government of Narasimha Rao and nobody else who came in between took the least effort to get at the truth of the matter. All that they were interested in reading the "Indian Express" or the "Hindu". And, Sir, I also want to make a very important point here. Whatever Press reports that come out on the Bofors issue are carefully timed and they are coincidence of various vested interests and various unholy alliances and they are carefully timed. You take the "Hindu" report. It came at the time of the Mamallai Nagar AICC Conference and, after that, every report that has been coming is timed very carefully. Even the great Chitra Subramaniam, whose book is the Bible to this Opposition, has said that the people in the "Hindu" manipulated the timing of the report and they did not allow her to report the matter as and when she got it. Even the great Chitra Subramaniam has said it.

SHRI V. GOPALSAMY : You rely on Chitra Subramaniam ?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : No .....*(Interruptions)*.....

SHRI V. GOPALSAMY : Then why are you quoting her ? .....*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Please do not interrupt her.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : Mr. Gopalsamy, please do not interrupt me. I am mentioning her name because none of you has read Chitra Subramaniam's book. I have read that book and I am not relying on it. I reject the book as rubbish. What I am saying is that the Opposition is relying on her book and you don't even know that this is what she has said. You are relying on Press reports. That is the tragic position which the Indian Opposition has fallen into. Such efforts as were made on the Bofors issue were made by the Rajiv Gandhi Government and the present Government headed by Shri Narasimha Rao and, in this connection, I would like to draw the attention of the House to certain basic facts.

Sir, the issue broke out in 1987 and from that moment onwards, Shri V. P. Singh and his cohorts were trying to sensationalise the matter. Mr. V. P. Singh was the Finance Minister then—we had been tricked and nobody mentions this—and he signed the documents on the Bofors case even though he knew nothing of what he was signing. He was the most amazing Finance Minister because he was signing on a blank paper. So, such mistakes were made and he was a party and he was responsible. But the moment he found that he could not take on our leader, the late revered Rajiv Gandhi, he fooled him completely and then he came out of the party and started raising the issue.

Sir, in 1990, ...*(Interruptions)*.....

SHRI V. GOPALSAMY : For what reasons .....*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Gopalsamy, please do not interrupt.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : Sir,

I have no objection to Mr. Gopalsamy speaking. Let him say whatever he wants to say when his chance comes .....*(Interruptions)*.....

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir with you in the Chair, there should be no civil war between two Members from Tamil Nadu! .....*(Interruptions)*.....

SHRI V. GOPALSAMY: I only want to know from Mrs. Jayanthi Natarajan for what reasons Mr. Arjun Singh .....*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mrs. Natarajan, are you yielding? .....*(Interruptions)*..... She is not yielding. So, I cannot allow you, Mr. Gopalsamy.....*(Interruptions)*..... She is not yielding.

SHRI V. GOPALSAMY: She has yielded. Then only I got up .....*(Interruptions)*..... She has yielded. Only Mr. Ahluwalia is instigating her not to yield.....*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gopalsamy, kindly take your seat .....*(Interruptions)*.....

SHRI V. GOPALSAMY: For what reasons Mr. Arjun Singh submitted his resignation?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gopalsamy, please sit down .....*(Interruptions)*.....

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, it was in November 1988 that the CBI, under the Prime Ministership of the late Rajiv Gandhi, started the investigation into the Bofors issue and the most important thing was that it was the Government headed by the late Rajiv Gandhi that signed a Memorandum of Understanding with the Swiss Government. No such Memorandum had ever existed before. It was the Rajiv Gandhi Government that signed the Memorandum of Understanding with the Swiss Government in order that this investigation might be facilitated and also to facilitate the other things. Meanwhile, — my colleague, Mr. Ahluwalia, has already gone into great detail — because of the expedient politics, because of the back-stabbing practice of Mr. V. P. Singh and his friends, it became such a sensational issue.

SHRI V. GOPALSAMY: He is a man of courage. He need not stab in the back .....*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gopalsamy, if you go on interrupting like this, I will not call your name. You are also here; your name is also there. You will not be called when your turn comes .....*(Interruptions)*.....

SHRI V. GOPALSAMY: What is this, Sir? If you say that I should not interrupt, it is all right and I will not interrupt. But you are saying that you will not call my name. What is this .....*(Interruptions)*..... This is not fair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I meant that I would take out that much time from your time.

SHRI V. GOPALSAMY: This is not fair, Mr. Vice-Chaiman .....*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly don't say that .....*(Interruptions)*..... Kindly don't say that. I request you not to interrupt. I am requesting you not to interrupt.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chaiman, Sir, I am very sorry.....*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gopalsamy, I requested you not to interrupt. But you had been doing it. Therefore, I made that remark.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, kindly speak now.

SHRI V. GOPALSAMY: She was enthusiastically listening to my interruptions.

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI (Orissa): Tamil Nadu is in the Chair, Tamil Nadu is speaking, and Tamil Nadu is intervening. What is this?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Mr. Gopalsamy says that he has a lot of respect for the Chair. I wish he would have an equal amount of respect for a colleague's right to speak in the House.

SHRI V. GOPALSAMY: Madam, I do not interrupt you hereafter.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Thank you, very much. I think, my persuasive tactics are better than those of the Chair.

Sir, I just said that it was Rajiv Gandhi's Government that signed the Memorandum of Understanding with the Swiss Government for

the exchange of information. Sir, then this issue was sensationalised by Shri V. P. Singh. Of course, as Mr. Ahluwalia has said, Shri V. P. Singh not only said that he had Rajiv Gandhi's Swiss bank account in his pocket, but, in fact, the main plank on which they came to power was that they said, "in 15 days we will find the culprits in the bofors case and we will bring them to book." Sir, they cheated the country, they fooled the country. Six years have passed and nothing has happened till now. Nobody has found out anything. This is what the Government of Shri V. P. Singh did. And this is how they cheated the people of India, and now they are attempting to cheat the people of India again by doing this. Sir, what happened when Shri V. P. Singh came to power? What happened in those 11 long months except for the quarrels between Mr. Devi Lal and Mr. V. P. Singh and the various leaders of the Opposition? Nothing happened on Bofors..... *(Interruptions)*..... Yes, nothing happened on Bofors, Mr. Jaipal Reddy. This is what I am saying.

SHRI S. JAIPAL REDDY: An FIR was filed. The Criminal Procedure Code was amended. Letter rogatory was sent. We won in the Geneva Cantonal Court and in the Federal Court of Switzerland. We got the papers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Reddy....

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, I want to plead with Mr. Jaipal Reddy to find out whether he respects may right as a Member to speak, as Mr. Gopalsamy does, or he does not have any respect..... *(Interruptions)*.

Sir, when Mr. V. P. Singh became the Prime Minister, what happened? The only thing that happened was, first of all, on 9-2-1990, letters rogatory with great fanfare and publicity were sent. And these letters rogatory were sent to the Swiss court to ask them to part with information. What happened to these letters rogatory? The whole Government that came to power on the promises made to the people of India, they all put their collective wisdom into this drafting. What happened to these brilliant letters rogatory? They were rejected because they were defective. This is the respect that the Swiss court had for Mr. V. P. Singh Government. And this is the brilliant activity that was done by the V. P. Singh Government. This is what Mr. Mathur was talking about. What happened to these letters rogatory? They were rejected by the Swiss court as defective. When were they rejected by the Swiss court? They were rejected by the Swiss court on 9-2-1990. It was on the 9th February, 1990. For eight long months they were ducking. You would imagine that the people who came to power, riding on the Bofors wave, who are so worked up for getting at the truth now, would have leaped into action for correcting the mistake. You would imagine that they would leap into action and immediately correct the mistake and go back to the Swiss courts with the problem. But no, Sir. For reasons best known to themselves, they never worked to correct the defects in their own letters rogatory. They sat on it for eight long months. Sir, when I was going through these details, I for my part wondered why Mr. V. P. Singh did not act on these letters rogatory, to correct these letters rogatory as soon as he knew that they were defective. Finally, Sir, I found my answer in a statement made by no less a person than somebody who was the Law and Commerce Minister of India. The then Law and Commerce Minister of India, on the 22nd December, 1990, addressing the Press Club of India said that both...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Who was the Minister?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Mr. Subramaniam Swamy.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Ah!

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: So what? But nobody denied what he said. You may or may not like Mr. Swamy. But, as the Law and Commerce Minister of India....

SHRI S. JAIPAL REDDY: Why were you hesitant to mention his name? Because of the high credibility that he commands?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I was going to mention. Dr. Swamy said as the Law Minister of India that Shri V. P. Singh and Shri Arun Nehru were deeply involved in this Swedish arms deal. And then a day before that, Mr. S. P. Malaviya who is here also told the reporters that no one was trying to hush up the Bofors case, and any allegations in this regard were baseless. If anybody disagreed with Dr. Swamy at that time, he could have easily come out with a statement or said something to that effect — I mean the Government.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I made a statement at that time.

SHRI V. GOPALSAMY: That Government was also your creation.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: They sat on it for eight long months and it was only on 30-8-1990 that amended letter rogatory was sent. This was the brilliance of the V. P. Singh Government. Then the whole matter went into the court. Cases were filed in the Delhi High Court to stop the proceedings. Appeals were filed by the beneficiaries in the Swiss court and then one thing happened. These appeals were rejected in the Swiss court, and on 13-12-90 bank documents were received which showed that more than seven lakh dollars were paid by Bofors to A.E. Services and an almost equal amount was transferred to a company called Colbar Investments. But the Government at that time never took any steps to find out the identity of Colbar Investments or whatever the company was in Panama and the matter rested there. It was not the Congress Government..... *(Interruptions)*..... Sir, I am not to answer Mr. Redddy. He can always say whatever he likes when he speaks. I am not the Minister to answer his questions.

Sir, cases were then filed in the High Court to stop the investigation and further action on the letter rogatory was, therefore, suspended. On 27th of August, 1991, the Supreme Court of India set aside these appeals. By that time, the Government headed by Shri Narasimha Rao had already come and taken over the reins of the Government. It was our Government. Whenever there has been any movement in the courts, this was at a time when our Government came into power and then pursued it. On 27th August, 1991, the Supreme Court set aside the appeals. Again on the 9th of September, Mr. Win Chadha went back to the court and filed another writ petition and that writ petition was also allowed by the Delhi High Court. This matter was pursued by the C.B.I. again in appeal and it was finally on the 17th of December 1992 that the Supreme Court finally disposed of all the cases and this was communicated immediately to the Swiss courts. It is now after the total procedue was followed and after the appeals were filed again in the Swiss court, as all of us know, that on the 29th of January 1993, the criminal court in Geneva dismissed all the objections by certain people and then lifted the stay on the letter rogatory. Appeals were also dismissed on the 20th of July, 1993 filed in this regard. Now, Sir, we are standing here because of what the Swiss courts have done. What has the Swiss court now said? I want to know the import of this judgment. I also read in the newspapers and I have come to this conclusion that what the Swiss court has done is this. The Swiss court has said: Lift the stay on the letters rogatory. Whatever letters rogatory have been sent by the Government of India, there is no stay on it, and they action proceeds on the Letter Rogatory. What does it mean? It means that the Swiss court has said, let the Government of India get whatever assistance it needs, whatever documents it needs from the Swiss courts, from the Swiss Government in trying to trace the culprits in the Bofors case. That is what the judgement is about. There is nothing more in the judgement. We are now going to pursue that judgement. There is no doubt that seven people trying to keep this secrecy appealed against the lower court's order lifting the stay. There is no doubt about it and the whole country wonders why these people were interested in getting a stay on the letter rogatory. We have to go into this matter. It is not something that I demand from the C.B.I. I would like the Minister to answer whether the C.B.I. has anything on record on any of these seven appellants and if there is anything on record, let us get into the bottom of the matter immediately. Let us find out if there is any evidence. The way the Opposition has reacted shows as if some wonderful new evidence has come up that immediately pinpoints the culprit. I am sorry, this is not correct. I appeal to everybody with folded hands. This is most unfair. This is in very bad taste. This is somthing which is there in black and white. This is something on which the Government is taking action. Let the judgment of the Swiss court come. Let us find out. Let the C.B.I. find out about these 7 people, how they were involved, etc. Let us get to the bottom of the case. Instead of this, you have been bandying names like Hindujas. Does Parliament deserve this? Why are you bandying names like Hindujas? The leaders of the B.J.P. also went to a party in the Hindujas' house in London. I am not going to talk about this. So many people have done. I do not want to talk about it because it is in very bad taste. I think it is in very bad taste.

Why are you talking about the Italian connection? I blush for the opposition. Can't you base your arguments on some facts? Do you have to hit below the belt? Is it the respect you pay to the memory of a dead man, a martyr to the nation, who was assassinated, and his family? Is it the only strategy you can think of? If we are to submit to this strategy and allow the

name of our great leader to be tarnished in this manner, I think it is better to hand over the Government to them and go away. This is most disgusting. All the time making snide remarks about the Italian connection. This is totally disgusting and it does the opposition no credit. Finally, about newspaper reports. My friend has said that the Swedish court has made some terrific castigation of Indian newspapers also. I do not know. I only want to say this. I would like the hon. Minister to investigate as to how these reports have come out. How did the newspapers get the report even before the C.B.I. got it? There is a great danger happening in this. What the opposition and the newspapers are trying to do is really to block the investigation. I feel that if the news leaks out beforehand, even before the C.B.I. gets hold of the news, they would not be able to conduct the investigation because the culprits would get the news and they would remove all the vital documents; they would block the investigation.

Therefore, I would appeal to the newspapers as well as the opposition to be more responsible. Let us help the investigation. Let us adopt a constructive attitude towards the investigation. Most important of all, let us behave with a modicum of good taste and decency in Parliament. Thank you.

SHRI V. GOPALSAMY: Madam, I kept my promise.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Thank you.

SHRI RAM JETHMALANI (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, never before have I felt so weak and feeble as I feel today. I almost feel like Arjuna on the battlefield, as I see, ranged against me on the other side, persons who are all my friends.....

SHRI V. GOPALSAMY: Arjuna was victorious.

SHRI RAM JETHMALANI: ... some of whom I have the honour to claim as my very dear friends, particularly, the three distinguished ladies who adorn the treasury benches.....

SHRI M. A. BABY (Kerala): How many clients are there that side?

SHRI S. S. AHLUWALIA: They are all there.

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I have heard them with rapt attention, which is due to such distinguished speakers. I tend to agree with some of the points that have been made both by Mr. Ahluwalia as well as the distinguished lady who just spoke.

I am trying to be, as far as possible, non-controversial. I fully understand the tremendous emotional attachment you have for your great leader and whose memory I respect, particularly, the tragic end that he met. These are not matters which any human being is likely to forget. But today, in a sense, is a happy day because what your great leader wanted to happen has happened, or, almost showing the prospect of happening. I would like to recall the words of your great leader which he uttered on the floor of the House. He said: 'I have repeatedly told both the Houses that if an enquiry establishes that any person has been guilty of receiving illegal payments... the strongest action under the law will be taken; that the Congress and its Government are as interested as anyone else in finding out the truth; let all sections of the House co-operate in this common task.

Sir, I do not wish to go into who frustrated the investigations. I do not wish to go into the question as to who has caused all the delay in the discovery of truth or in the fruition of the late Mr. Rajiv Gandhi's wishes in this matter. But there are certain salient facts which cannot be forgotten. The first fact is that when these allegations were made, whether these allegations are true. And I agree with both Mr. Ahluwalia and the distinguished lady that not until the final Court of this country has pronounced the person guilty, shall I call that person a guilty person. That is the rule of my professional ethics, a rule which I have tried to observe all along but in the observance of which I have been grossly impeded at various times by the gentlemen sitting opposite. I have always believed that no one man shall ever be condemned by the press or by anybody else until his guilt has been established by the last Court of the country. My friend, Mr. Ahluwalia, is right that the Swiss Federal Court has not found anybody guilty. I want to resolve this misunderstanding. It is a misunderstanding which I confess has permeated into the ranks of Opposition and also some members of the press and it must be made clear. It is true that all that the Swiss Federal Court has done is to remove all legal hurdles in the way of assistance being given to the investigating agencies in India for the discovery of the real culprits. What was being refused before is being offered to us. That

which is offered will still have to be taken; that which is offered in the Swiss form will have to be translated into legal admissible material under the Criminal Procedure Code. Chargesheets will have to be filed and, however much I might arrive at or I might have already arrived at moral conclusions about some people's guilt, in the eye of law, as I said, I shall never never say that so and so is guilty. But as equally I concede your point, I hope you will concede mine that investigations can only proceed on reasonable suspicion of guilt. And if the circumstances disclose not merely a reasonable amount of suspicion but they disclose so much suspicion—and the suspicion is so strong that in the mind of at least a layman it amounts to almost a moral conviction of gulit—then the investigation must at least proceed.

So, Sir, when the Opposition is raising what you call, noise, all that the Opposition is struggling to say is that now some light has been offered by the Swiss Court, please do not covertly allow this opportunity to go by, seize that light, bring that light to India and then carry on further investigations. But, Sir, there are certain special facts in this case where the finding of the Swiss Court, though of a very limited nature—strictly speaking, it is only a finding that they have decided to give you assistance in the matter of investigation—must be understood by my learned friends. In the peculiar facts of this case, the judgement of the Swiss Court has this significance which I want both my learned friends to understand. The letter rogatory issued from India had asked for attachment of those accounts into which the Bofors moneys had flown during the particular relevant period of 1986-87.

5.00 P.M.

Now that the appeals have been dismissed and the Swiss Court has said that they would give us that material, there is not merely a finding that they are going to offer us assistance but they are also telling us that available with the Swiss are the Swiss accounts into which Bofors money has passed during the relevant time, that is, the year 1986-87. Now, Sir, normally the courts in Switzerland do not disclose the names of the appellants. When the accused in this case or the suspects in this case....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Jethmalani, just one minute. I have to adjourn the house at five. How much time will you take? ...*(Interruptions)*....

SHRI V. GOPALSAMY: It was decided in the business Advisory Committee that today the debate on Bofors will be finished and we can sit late.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gopalsamy, I have no knowledge of that so far. ...*(Interruptions)*....

SHRI M. A. BABY: Honourable Vice-Chairman, in any case, let not the flow of the debate be interrupted.

SHRI KAMAL MORARKA: At least Mr. Jethmalani should be allowed. ...*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I would like to take the sense of the House. If the House agrees. ...*(Interruptions)*....

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, my humble request is, I want to go to the JPC. I want to hear everything.

SHRI RAM JETHMALANI: What do you want me to do, Sir? Do you want me to resume tommorrow? ...*(Interruptions)*.... Whatever you decide, I am entirely in your hands.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Let him complete.

AN HON. MEMBER: Tomorrow.

SHRI M. A. BABY: Tomorrow being a Private Members' day, there will be pressure on time. Please keep that also in mind.

SHRI V. GOPALSAMY: That's why we raised the matter in the Business Advisory Committee meeting. Tomorrow being a Private Members' day, it will not be possible. Therefore it was decided....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANSAMY): Mr. Gopalsamy, I have heard whatever you have said, but I have no knowledge of it. Mr. Jethmalani, if the House agrees, you can continue now.

SHRI RAM JETHMALANI: Thank you, Sir, I am obliged to you.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH

ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Mr. Jethmalani, I don't want to interrupt you, but I just want to know: Does it mean that the debate will be completed today, replied to today and we will sit late or is it that Mr. Jethmalani will finish his speech? ...*(Interruptions)*....

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I am sorry, are you going to hear Mr. Jethmalani or are you going to hear me? ...*(Interruptions)*....

SHRIMATI MARGARET ALVA: I would like the House just to decide how long we are going to sit.... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANSAMY): It is entirely up to the House to decide. Is it the sense of the House that we continue and complete the discussion today or.... *(Interruptions)*.... One minute, Mr. Gopalsamy, I have to take the sense of the House. Or, can we adjourn the House now? ...*(Interruptions)*.... Then we have to complete the discussion today.

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): This is an important debate and the debate now should be adjourned till tomorrow.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Tomorrow is a Private Members' day.

SHRI V. GOPALSAMY: The Minister was present in the Business Advisory Committee meeting.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I was not present. ...*(Interruptions)*....

SHRI M. A. BABY: We should take it up on Monday.

SHRI V. GOPALSAMY: There is no sitting on Monday.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANSAMY): That will be decided by the Chairman ...*(Interruptions)*.... Kindly don't interrupt me. Now the sense of the House is that the House has to be adjourned. The House is adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at five minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 30th July, 1993.